[Shri P. M. Sayeed]

been eclipsed by the colossal tragedy on the eastern coast.

We do not have on Assembly; we are directly under the Central rule. Our smallness and our location might have been the reasons for the fact that nobody in authority from the centre or the mainland visited us in this hour of our need.

I am not saying this as a complaint or in anger. I am only saying this out of a feeling of helplessness and loneliness.

Whatever that may be, I request the Government, Sir, to urgently take some steps to help those people in that island.

Firstly, let there be a medical team. Also let there be more supplies of food articles— not only grain. Let there be supply of building material— cement, timber, tiles, lime, asbestos etc.

Secondly, please send some soil scientists. Let them test the soil and suggest something to make it fit for cultivation. Then, rush coconut seedlings, other seeds and fertilizers

Thirdly, please give them fishing boats and also two big boats so that inter-island traffic could be re-established. Now, not only the mainland but even we in the other island are helpless to help our brethren.

Sir, I hope the Government will take these measures. Let it not be said that those people who had survived the cruelty of nature were doomed by the inaction of men. Just because we are small and away, let us not be forgotten.

17.29 hrs.

(ii) ACCUMULATION OF STOCKS IN SOME SICK ILKTELE MILLS

श्री हकमचन्द कछवाय (उज्जैन) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को नियम 377 के अन्तर्गत उठाने जा रहा हूँ, श्रच्छा होता कि सम्बन्धित मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित होते—इस बात का मुझे बहुत दुःख है।

भारत सरकार ने देश की 103 कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लिया है। ये मिलें प्रतिवर्ष 42 करोड़ रुपये का घाटा देती जा रही है और यह घाटा दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस का मूल कारण है कि इन मिलों के अन्दर टेक्निकल लोग ज्यादा नहीं हैं, अफसर ज्यादा भर गये हैं, जिन्हें वस्तुस्थिति का कोई ज्ञान नहीं है और कपड़ा बेचने की जो पोलिसी है, जो वितरण व्यवस्था है, उस में नानाप्रकार की त्रुटियाँ हैं। उसी का परिणाम है कि तमाम मिलों में बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा जमा होता जा रहा है, जिस में ए.जी.जाम होनी जा रही है। जब कि कोई भी कन्ट्रोल का कपड़ा मार्केट में मिलता नहीं है, आप दिल्ली शहर में ही देख लीजिए कन्ट्रोल की धोती पहनने को नहीं मिलती है। यह स्थिति आज सागरे देश में है। ऐसा क्यों है ?

व्यापारी एन० टी० सी० की मिलों से कपड़े का मोटा करता है, लेकिन अगर दो पैसा बढ़ जाए तो त्रिम से मोटा किया होता है, उस का मोटा एन० टी० सी० द्वारा रद्द कर दिया जाता है और दूसरे को मान दे दिया जाता है। अपनी बात के पक्के नहीं है, जिस से दलाल और व्यापारी दानो उन में नाशुण है। कपड़ा बेचने में इस तरह की और भी अनेकों त्रुटियाँ हैं, जिन में मुशर्र होना बहुत बुरा है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ—मध्य प्रदेश की कुछ मिलों ने कलकत्ता की एक पार्टी को कपड़ा बेचा—पार्टी का नाम है—राज लक्ष्मी एमोसियेट्स कलकत्ता—इन के साथ 50 लाख रुपये का मोटा हुआ, लेकिन इन से केवल 15 हजार रुपये डिपोजिट रखवाया। 50 लाख का कपड़ा बेच दिया और जब वह कलकत्ते पहुँच गया, तो उस व्यापारी ने उस कपड़े को लेने से इनकार कर दिया। महीनों हमारा कपड़ा वहाँ पड़ा रहा और इस में हमें काफी घाटा हुआ। उसने बिन्टी छुड़वाई नहीं और हमें डेप्युरेज देना पड़ा और उस कपड़े को

ले कर बापस आना पड़ा, कुछ सस्ते दामों पर बेच दिया। ऐसी स्थिति है।

इतनी ही नहीं बल्कि जो माल खरीदा जाता है, उस में भी नाना प्रकार की वृष्टियाँ हैं। कैमिकल का माल, काटन का माल या मशीनरी में लगने वाला जो सामान है, वह घटिया किस्म का लिया जाता है और जैसे ज्यादा दिये जाते हैं। ऐसे अनेक प्राप को उदाहरण मिलेंगे।

इन मिलों के अन्दर कुछ मान्यता प्राप्त यूनियनों काम करती हैं लेकिन वे ठीक प्रकार से काम नहीं करती। मशीनों बन्द रहती हैं और पिछली सरकार की शरण में चलने वाली मान्यता प्राप्त यूनियन जो हैं, उस के वर्कर और मैम्बरों जो मिलों में काम नहीं करते और फीकट की तन्स्वाह लेते हैं। अगर किसी मिल में 3 हजार श्रादमी काम करने हैं तो उन में से 500 ऐसे श्रादमी प्राप को मिलेंगे जो बिना काम करे बतन लेते हैं। प्राप इसकी इन्स्वायरी करा कर पता लगा सकते हैं। चार सार्चों का समझौता हुआ था मान्यता प्राप्त यूनियन से, लेकिन उन्ही मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा रद्द किया जा रहा है जिससे काफी मशीने बन्द रहती हैं और मिलों में घाटा हो रहा है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि सरकार ऐसी पालिसी बनाए जिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। जनता पार्टी की सरकार ने अधिक लोगों को रोजगार देने की बात कही है। अगर इन सब मिलों में चार शिफ्टें छः घंटे की चालू कर दी जायें, तो बहुत से लोगों को काम मिल जाएगा। मैं इस का विरोधी नहीं हूँ। इस से उत्पादन भी अच्छा होगा परन्तु यूनियनों के झगड़े नाना प्रकार के हैं और हमारे जो आई० ए० एस० आफिसर्स हैं, वे उन को समझ नहीं पाते हैं जिस का परिणाम यह होता है कि प्राप दिन हड़ताल होती रहती हैं। जो यूनियनों पहले हड़ताल का विरोध करती थीं, प्राप वे विरोध में आने के कारण हर जगह उद्योगों में

हड़ताल करवा रही हैं चाहे वह बम्बई हो, कलकत्ता हो, कानपुर हो या मध्य प्रदेश हो, सो किसी भी प्रान्त की मिलें हों, हड़तालें हो रही हैं। इस से उत्पादन की क्षति होती है और तोड़फोड़ भी होती है। यह सारी स्थिति प्राप है। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार का ध्यान खीचना चाहता हूँ कि प्राप जो अफसर एन० टी० सी० में बैठे हुए हैं, वे अव्यय्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्राप ने सुना होगा कि हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र के श्री दीक्षित सेक्रेट्री हुआ करते थे। उन्होंने बहुत धपले किये हैं। और बहुत प्रकार का गबन किया है। उन को इस का डिप्टी चेयरमैन बना कर रखा है। मेरा कहना यह है कि जो टैक्नीकन श्रादमी हैं उन्हें काम सौंपा जाए। टैक्नीकन लोगों को बूढ़ कर ऐसे काम पर लगाया जाए और उन से यह काम लिया जाए और पुराने अधिकायियों को निकाला जाए। अगर ऐसा होगा तो मुझे विश्वास है कि 103 मिलें जो देश के अन्दर हैं, वे अच्छी चलेंगी और उन को मुनाफा होगा।

इस के अलावा वितरण में और माल के बेचने की व्यवस्था में सुधार हो और माल खरीदने में जो वृष्टियाँ हैं, उसे ठीक किया जाए। अगर मिलों के अन्दर सुधार होगा, तो मुनाफा होगा और प्रतिवर्ष जो घाटा बढ़ता जाता है वह नहीं होगा। अगर इसी तरह से घाटा बढ़ता रहा, तो यह एक बहुत बड़ा अभिशाप जनता सरकार पर होगा कि इतना घाटा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो चार शिफ्टों का सुझाव दिया है और अधिक लोगों को काम देने के लिए कहा है, उस पर सरकार ध्यान देगी और मेरे सुझावों को मानेगी।

17.34 hrs.

(iii) ATTACK ON INDIAN EMBASSY OFFICIAL IN WASHINGTON

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tiruchirapalli): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not know whether any useful purpose will be served by my